



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 13, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-49

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	619-644	1500
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आझाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	797-802	1500
भाग 2—आझाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	413-422	975
स्टोर्स पर्वज-स्टोर्स पर्वज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## औद्योगिक विकास अनुभाग—2

कार्यालय ज्ञाप

25 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या:—1269/VII-A-2/2021/11(सिडकुल)/2021—चूँकि, प्रदेश में सिडकुल एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा निजी निवेशकर्ताओं/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/पट्टाधारकों/आपूर्तिकर्ताओं/ सलाहकारों के मध्य लम्बे समय से चल रहे वित्तीय विवादों के दृष्टिगत एक निपटान तंत्र (Conciliation Mechanism) की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "Ease of Doing Business" की भावना के अनुकूल एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय—समय पर यथासंशोधित)" के प्रावधानों एवं नीति आयोग, भारत सरकार की संस्तुति के आलोक में, स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक सुलह समिति (CCIE) बना कर लम्बित वित्तीय विवादों का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाय, ताकि प्रदेश में निवेश एवं विकास कार्यों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निजी सहभागिता हेतु अनुकूल वातावरण सृजित हो सके;

अतएव श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में, नीति आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14070/14/2016-PPPAU, दिनांकित 05.09.2016 के साथ नीति आयोग के कार्यालय परिपत्र संख्या-N-14070/04/ 2021-PPPAU, दिनांक 20.07.2021 के द्वारा परिचालित स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सी0सी0आई0ई0) के गठन एवं समिति की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में ड्राफ्ट रिपोर्ट के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संलग्नानुसार "उत्तराखण्ड के सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों/ उद्योगपतियों/ ठेकेदारों/ रियायतियों/ पट्टाधारकों / आपूर्तिकर्ताओं/ सलाहकारों आदि के साथ विवादों के सुलह एवं समाधान हेतु व्यवस्था" बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।



(उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1269 दिनांक 25/10/2021 का)

### औद्योगिक विकास अनुभाग-2

#### उत्तराखण्ड शासन

#### स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) का गठन

**विषय :** उत्तराखण्ड के सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/पट्टा-धारकों/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों आदि के साथ विवादों के सुलह एवं समाधान हेतु व्यवस्था।

#### 1. परिभाषाएं :

- (क) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड की सरकार/शासन अभिप्रेत है;
- (ख) 'सरकारी संस्था' से उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/परिषद/निगम/अन्य संस्थायें, अभिप्रेत है;
- (ग) 'विकासकर्ता' से सभी निवेशक/उद्योगपति/व्यवसायी/ठेकेदार/रियायती/पट्टाधारक/ सलाहकार आदि, जो सरकारी संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं/सेवाओं को संपादित/ निष्पादित करने में संलग्न हैं, अभिप्रेत है;
- (घ) 'सी.सी.आई.सी.' से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित की जाने वाली स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) 'परियोजनायें' से सरकारी संस्था द्वारा निष्पादित सभी निर्माण अनुबंध/ईपीसी अनुबंध/ सार्वजनिक निजी भागीदारी/सेवा/आपूर्ति अनुबंध अभिप्रेत है;
- (च) 'नोडल विभाग' से निदेशक, उद्योग (निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन, अभिप्रेत है;
- (छ) 'नोडल अधिकारी' से प्रत्येक सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता और सुलह समिति के साथ संवाद करने के लिए घोषित किया गया अधिकारी, अभिप्रेत है;
- (ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से मुख्यमंत्री/मंत्री/सचिव/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभिप्रेत है;
- (झ) 'सुलह के लिए सहमति' से अधिनियम और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सुलह के लिए सरकारी संस्था और विकासकर्ताद्वारा अनुमोदित स्वतः सहमति, अभिप्रेत है;
- (ट) 'समाधान' से सीसीआईई के समक्ष विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा आपसी सहमति से नियत नियम और शर्तें अभिप्रेत है;
- (ठ) 'अधिनियम' से माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है।

#### 2. उद्देश्य :

राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक सुविकसित बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण कारक है। विगत वर्षों में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ताओं के साथ समझौते किए गए हैं, जिनमें सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के बीच विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। लंबित विवादों और दावों की समस्या ने गंभीर रूप धारण करते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के साथ-साथ परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी प्रभावित किया है।

अतः, उत्तराखण्ड शासन द्वारा व्यापार में आसानी और रोजगार सृजन के लिए 'निवेशक अनुकूल वातावरण' विकसित करने के निमित्त सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के मध्य विवादों के सुलह और समाधान हेतु 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया है।



**उदाहरण :**

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न प्रकार से कियान्वयन हेतु (आइटम की दर, संयुक्त उद्यम, ईपीसी, आदि)राज्य की ओर से विकासकर्ता के साथ विभिन्न अनुबंध/समझौते किए गए हैं। इन अनुबंधों/समझौतों के अंतर्गत कई विवाद उत्पन्न हुए हैं जिनमें न केवल अत्यधिक कानूनी व्यय शामिल है, बल्कि इन विवादों में शामिल दोनों पक्षों के बहुमूल्य मानव और प्राकृतिक संसाधनों का भी व्यपवर्तन हो रहा है। वर्तमान में, विभिन्न माध्यस्थता अधिकरणों को 11 प्रकरण सन्दर्भित किए गए हैं, जिनमें कुल दावा राशि रु. 485 करोड़ निहित है। विवादों का शीघ्र और अदालत के बाहर समाधान सभी हितधारकों और राज्य की प्रगति के हित में है।

**3. पृष्ठभूमि :**

- 3.1 नीति आयोग के कार्यालय झाप संख्या 14070/1412016-पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 के द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआईए) द्वारा "निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार के उपायों पर पहल" शीर्षक के साथ लिये गये निर्णय को सभी सम्बन्धितों/विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भेज कर उसमें निहित पहलों पर शीघ्र विचार करने और उनके कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। इन पहलों में, लंबित या नए मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति' की नियुक्ति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विवादों के समाधान की एक प्रणाली को स्थापित करना भी सम्मिलित है।
- 3.2 नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय झाप सं0 एन0 14070/04/2021-पी.पी.पी.ए.यू. दिनांकित 20 जुलाई, 2021 (झापट रिपोर्ट) द्वारा समाधान तंत्र की स्थापना तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 3.3 उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति आयोग के द्वारा निर्गत विवादों के समाधान हेतु तंत्र स्थापना एवं प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सीसीआईई को सन्दर्भित किया जा सकता है।

**4. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति :**

- 4.1 सीसीआईई में सामान्यतया 3 सदस्य होंगे।
- 4.2 समिति के सदस्यों का नामांकन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा एवं सुलह हेतु इच्छुक सम्बन्धित विकासकर्ता/अन्य पक्षकार की उपरोक्त सुलह समिति पर सहमति प्राप्त की जायेगी। जिन विकासकर्ता/अन्य पक्षकार के द्वारा सुलह समिति पर सहमति दी गयी है तो यह सहमति माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996(समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 एवं 64 के अन्तर्गत सहमति समझी जायेगी।
- 4.3 सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्तें वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।
- 4.4 सी.सी.आई.ई से सम्बन्धित व्यापक 'नियम एवं शर्तें' तथा कार्यक्षेत्र (T&R) अनुलग्नक-1 में होगी। तदनुसार विकसित की गयी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को सुलह की कार्यवाही में लागू माना जायेगा।
- 4.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन सीसीआईई के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा जोकि सुलह समिति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सचिवालयी सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। ऐसी व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा छमाही आधार पर की जाएगी।

**5. सीसीआईई की कार्यप्रणाली :**

- 5.1 सुलह प्रक्रिया, 'माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के भाग-III के अधीन संचालित की जाएगी।



- 5.2 सीसीआईई, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुलग्नक-2 में यथानिर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार संचालित होगी।
- 5.3 समिति की किसी भी कार्यवाही के दौरान सदस्यों में से किसी एक के उपलब्ध न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अन्य दो सदस्यों वाली समिति मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए सक्षम होगी और समिति की कार्यवाही दूषित नहीं मानी जायेगी यदि तीन सदस्यों में से एक समिति के विमर्श में उपस्थित नहीं है। तथापि, दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, सभी 3 सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे और ऐसा समझौता दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- 5.4 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) या तो पक्षों के बीच विवाद (विवादों) को सुलझाने और निपटाने में सफल होगी या फिर यह प्रक्रिया विफल हो सकती है। सीसीआईई के स्तर पर सुलह प्रक्रिया की विफलता की स्थिति में, पक्षकार सुलह प्रक्रिया से हट सकते हैं और मध्यस्थता/न्यायालयों की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। सुलह की कार्यवाही सफल होने की स्थिति में, विवाद के पक्ष लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे। ऐसा समझौता 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996(समय-समय पर यथासंशोधित)' की धारा 73 के संदर्भ में पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

#### 6. माध्यस्थम् अधिकरणों, न्यायालयों के समक्ष पहले से लंबित मामलों में प्रक्रिया :

- 6.1 माध्यस्थम् अधिकरणों या न्यायालयों के समक्ष लंबित विवादों के मामलों में, सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता को अथवा विपरीततः, अनुलग्नक-3 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आगे आने और सुलह समिति के माध्यम से सुलह की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रस्ताव दिया जायेगा। सरकारी संस्था तथा विकासकर्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुलह समिति को अनुलग्नक-4 के अनुसार संयुक्त सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे जिस पर समिति ऐसे संदर्भ (संदर्भों) की जांच प्रारम्भ करेगी। जब भी पक्षकार सुलह समिति से समाधान हेतु सहमत होते हैं, वे सम्बंधित माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- 6.2 समाधान हो जाने की स्थिति में पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/मध्यस्थता प्रक्रिया से 30 दिनों के भीतर मामला वापस लिया जायेगा।

#### 7. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) की सिफारिशों पर नोडल विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई :

- 7.1 सरकारी संस्था और विकासकर्ता सीसीआईई के सिफारिशों/निर्णयों का सम्मान और क्रियान्वयन करेंगे।
- 7.2 सीसीआईई की सिफारिश/निर्णय प्राप्त होने पर नोडल विभाग द्वारा 7 कार्य दिवसों के भीतर, सरकारी संस्था और विकासकर्ता को विवाद, दावा राशि, निपटान राशि आदि के संक्षिप्त विवरण सहित सूचित किया जायेगा।
- 7.3 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा सीसीआईई के निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जायेगी।
- 7.4 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने और माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले को यथासंभव 30 दिन के भीतर वापस लेने, यथा लागू आदि दायित्वों को पूर्ण करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। निपटान के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय भुगतान/वचनबद्धता की पूर्ति, निपटान तिथि से 30 दिनों (अथवा परस्पर सहमति की अवधि) के भीतर सम्बंधित पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है और यदि विकासकर्ता इस प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए सहमत नहीं हैं या कोई संकोच है, तो कोई बाध्यता नहीं है और उन्हें अन्य संगत कानूनी अनुतोष प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।



## अनुलग्नक : 1

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के सामान्य नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) तथा कार्यक्षेत्र (Terms of Reference):

1. तीन सदस्यीय सीसीआईई का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्तें वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।
3. सुलह प्रक्रिया, 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के भाग III के तहत निष्पादित की जायेंगी।
4. सीसीआईई के एक सदस्य को कार्यवाही के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 25000/- मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
5. सुलह समिति द्वारा अपनी पहली बैठक में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को निर्धारित किया जा सकेगा।
6. सीसीआईई द्वारा देहरादून में एक उपयुक्त स्थान पर अपनी दैनिक बैठकें आयोजित की जायेंगी और कार्य की अधिकता/व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हर महीने जितनी उचित समझे, उतनी बैठकें आयोजित की जायेंगी। यह अपेक्षित है कि सुलह-सह-निपटान की कार्यवाही प्रत्येक मामले में 5 बैठकों के माध्यम से, किन्तु सीसीआईई को संदर्भ प्राप्त होने के दिन (संयुक्त सहमति पत्र प्राप्त करने की तिथि) से जो तीन महीने से अधिक नहीं होगी, की अवधि में पूरी की जायेगी। असाधारण मामले में, यदि किसी विशेष विवाद के लिए 5 से अधिक बैठकों की आवश्यकता होती है, तो समिति के विवेक पर केवल 7 बैठकों के लिए मानदेय के भुगतान के प्रतिबंधाधीन यथासम्भव न्यूनतम अतिरिक्त समय के साथ ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।
7. सीसीआईई द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग से सौहार्दपूर्ण समाधान पर अपनी सिफारिशें दी जा सकती हैं।
8. सीसीआईई द्वारा संदर्भित मामलों के निस्तारण के लिए अपनी कार्यपद्धति/प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। पक्षकारों को स्पष्टता हेतु यह उल्लेखनीय है कि सीसीआईई की प्रक्रिया वैकल्पिक मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में नहीं है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावों/बचाव, तर्कों, प्रत्युत्तरों, लिखित निवेदनों आदि के साथ आते हैं। सीसीआईई का मंच एक समझौता मंच है, जहां पक्षकारों के मध्य कानूनी द्वन्द के बजाय आपसी समझदारी आधारित आदान-प्रदान की भावना महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे अपने-अपने रुख के संबंध में सीसीआईई के समक्ष संक्षिप्त में तथा सुलह/निपटान की भावना से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
9. सुलह कार्यवाहियों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, सुलह समिति द्वारा राज्य सरकार या उसकी संस्थाओं को अपने अनुबंध प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए समय-समय पर सलाह/सुझाव दिया जा सकता है।

**अनुलग्नक : 2****सुलह के लिए स्थायी संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :**

सीसीआईई द्वारा परियोजनाओं में विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

1. सुलह की प्रक्रिया 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित)' की धारा 61 से 81 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।
  2. अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सुलह की कार्यवाही का प्रारंभ :
    - (क) सीसीआईई के माध्यम से सुलह के लिए सहमति देते हुए, विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र (अनुलग्नक-4)।
    - (ख) विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा सुलह के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों/विवादों का संक्षिप्त विवरण।
  3. विकासकर्ता एवं सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व :
    - (क) सरकारी संस्था : सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधितः अधिकृत प्रतिनिधि।
    - (ख) विकासकर्ता : सुलह समझौते में जाने के लिए विधितः विकासकर्ता द्वारा पारित प्रस्ताव और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत वरिष्ठ कार्यकारी या नियमित कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा। ऐसे प्रतिनिधि को विकासकर्ता के संकल्प और मुख्तारनामा की प्रति सुलह समिति की पहली बैठक में या उससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा (अनुलग्नक-5 और 6)।
- पक्षों को सुलह प्रक्रिया के दौरान कानूनी पेशेवर को नियुक्त करने की अनुमति नहीं होगी।**
4. सीसीआईई की पहली बैठक से पहले पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण/न्यायालय, यदि कोई हो, को उनके द्वारा सुलह प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित कर सकते हैं।
  5. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (प्रतीकात्मक, सीमित नहीं) :-
    - (क) अनुबंध/रियायत समझौते की प्रति।
    - (ख) दावे (दावों) का विवरण और प्रतिरक्षा(ओं) का विवरण।
    - (ग) माध्यस्थम् पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड), माननीय न्यायालय के समक्ष दायर विवरण, न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति।
  6. सीसीआईई द्वारा शीघ्रातिशीघ्र एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जायेगा। सीसीआईई द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु जल्दी-जल्दी बैठकें की जायेंगी।
  7. सीसीआईई, अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, जहाँ आवश्यक हो, दोनों पक्षों को समाधान की संभावित शर्तों के बारे में संस्तुति करेगी।
  8. सहायता (अधिनियम की धारा-68 के तहत): सुलह समिति को ऐसी विशेषज्ञ तकनीकी और सचिवालयी सहायता प्रदान की जायेगी जैसा समिति द्वारा दक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु अपेक्षित हो। नोडल विभाग द्वारा समिति की संतुष्टि के अनुरूप इसकी व्यवस्था की जायेगी।
  9. सुलह की लागत एवं जमा :
    - 9.1 नोडल विभाग, प्रथम दृष्टया, सुलह की कार्यवाही पर होने वाला सभी व्यय वहन करेगा जिसमें सुलहकर्ताओं को मानदेय का भुगतान, कार्यालय स्थान का प्रावधान, समर्पित विशेषज्ञ एवं सचिवालयी सहायता, और अन्य अनुषंगिक व्यय शामिल हैं। अन्य पक्ष (विकासकर्ता) द्वारा सुलह की



कार्यवाही शुरू करने के लिए नोडल विभाग में, यथासंभव अग्रिम रूप से, ₹ 3.00 लाख की राशि जमा की जायेगी।

- 9.2 नोडल विभाग द्वारा सुलह समिति की ओर से सुलह कार्यवाहियों पर हुए व्यय का लेखा-जोखा रखा जायेगा। सुलह की कार्यवाही समाप्त होने पर, नोडल विभाग सुलह की लागत का लेखा-जोखा सुलह समिति को प्रस्तुत करेगा, जिसे अंततः सुलह समिति के निर्देशों के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजित किया जाएगा।
10. अवशिष्ट मामले : सीसीआईई इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव के आधार पर समय-समय पर इस एसओपी की समीक्षा सहित किसी भी अवशिष्ट मामलों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। कोई भी परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।



## अनुलग्नक : 3

विभाग की परियोजनाओं में उत्पन्न विवादों के विवरण के साथ विकासकर्ताओं को भेजा जाने वाला पत्र।

संख्या :

तिथि :

विषय: .....विभाग, उत्तराखण्ड सरकार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सुलह समिति (सीसीआईई) की स्थापना।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी संस्था और विकासकर्ता के बीच किसी भी संदिदात्मक विवाद के समाधान के लिए प्रकरण सीसीआईई को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।

1. सुलह प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के समाधान और मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सीसीआईई के गठन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है। यह ज्ञातव्य है कि सीसीआईई का विस्तार माध्यम प्रक्रिया से पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् के विवादों में व्याप्त है।
2. सरकारी संस्था सभी संबंधित मामलों में जिसमें मा0 न्यायालयों के समक्ष इसके द्वारा माध्यम पंचाट को चुनौती दी गयी है, को सीसीआईई द्वारा समाधान हेतु लिए जाने वाले समय तक, अपनी सहमति से स्थगित करने के लिए मा0 न्यायालय से उचित अनुरोध करने को तैयार है, यदि आप इससे सहमत हैं।
3. यदि आप वर्तमान में माध्यम कार्यवाही के तहत लंबित विवादों को उक्त समिति को संदर्भित करने के लिए सहमत हैं, तो आप इस सुलह तंत्र का सहारा ले सकते हैं और माध्यम अधिकरण से यह अनुरोध कर सकते हैं कि जब तक कि सीसीआईई उक्त विवाद (विवादों) पर विचार करती है, तब तक निपटान की कार्यवाही को स्थगित रखने पर विचार किया जाए।
4. कृपया ध्यान दें कि सीसीआईई को विवाद (विवादों) को संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति/इच्छा देकर, आप सुलह प्रक्रिया हेतु, विशेष रूप से माध्यम और सुलह अधिनियम, 1998 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 और 64 में निहित प्रावधानों के लिए, अपनी स्वीकृति की भी पुष्टि कर रहे हैं और यह अधिनियम के तहत "सुलह" की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
5. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में विभाग के निम्नलिखित पते पर अपनी सहमति/इच्छा सूचित करने का कष्ट करें।

पता :

ई-मेल :

संपर्क नंबर :

भवदीय,

(विभाग के नोडल अधिकारी)

## अनुलग्नक : 4

सीसीआईई को सहमति पत्र (सुलह के लिए सहमति हेतु दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित)

माननीय स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के सम्मक्ष।

विषय: ..... (परियोजना का नाम) से संबंधित विवादों/दावों के निपटारे का प्रस्ताव

राज्य सरकार के कार्यालय झाप संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार इंगित विषय ..... (परियोजना का नाम) से सम्बन्धित विभिन्न विवादों/मुद्दों के समाधान के लिए प्राप्त सहमति के आधार पर दोनों पक्ष माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के भाग-III (समाधान) अनुसार सुलह के लिए सहमत हुए हैं। सुलह के लिए पक्षकारों की यह सहमति सीसीआईई द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली/मानक संचालन प्रक्रियाओं के प्रति भी सहमति है, जैसा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय झाप में स्पष्ट किया गया है।

विकासकर्ता

सरकारी संस्था

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

संपर्क विवरण :



**अनुलग्नक : 5**  
**बोर्ड संकल्प के लिए प्रारूप**

..... (विकासकर्ता का नाम) के निदेशक मंडल/न्यासी/सोसाईटी/अधिकृत पार्टनर/व्यक्ति (जिसे आगे 'अधिकारी' कहा गया है) द्वारा.....(स्थान) में दिनांक ..... को आयोजित बैठक में पारित संकल्प की सत्यापित प्रति।

"संकल्प किया गया कि श्री .....(नाम एवं पदनाम) (इसके बाद 'अधिकृत हस्ताक्षरी' के रूप में संदर्भित), जो कि .....के निवासी हैं, एतद्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के समक्ष उपस्थित होने, प्रतिनिधित्व करने और सुलह समझौता निष्पादित करने के लिए विकासकर्ता.....की ओर से विकासकर्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करेंगे।"

**परियोजना का नाम:**

इस अभिलेख द्वारा सभी सूचित होंगे कि हमारा .....(विकासकर्ता का नाम), जिनका पता ..... है, का प्रतिनिधित्व ..... (नाम व पदनाम जिसे आगे 'वरिष्ठ अधिकारी' कहा गया है) श्री ..... द्वारा किया जायेगा।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि विकासकर्ता की सहमति से श्री ..... को विकासकर्ता की ओर से ..... (अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम/पदनाम) के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित/प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त मुख्तारनामा पर विकासकर्ता के ..... द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

**नमूना हस्ताक्षर 1.**

2.

3.

**द्वारा प्रमाणित**

**हस्ताक्षर (वरिष्ठ अधिकारी)**

## अनुलग्नक : 6

## मुख्तारनामा के लिए प्रारूप :

## मुख्तारनामा

इस अमिलेख द्वारा सभी सूचित होंगे कि हम....., (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय/पत्राधार पता (बाद में 'पता' के रूप में सन्दर्भित)..... में है, के प्रतिनिधि श्री ..... पुत्र श्री....., जो वर्तमान में ..... में निवास कर रहे हैं, को हमारे द्वारा नियोजित किया गया है और अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में हमारे सच्चे और वैध कानूनी प्रतिनिधि हैं (आगे "एटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) और इस रूप में ..... (परियोजना का नाम) जिसे..... (सरकारी संस्था का नाम), द्वारा प्रस्तावित/विकसित किया जा रहा है, के सम्बन्ध में सी.सी.आईई के सम्पन्न गतिमान सभी मामलों में हमारी ओर से उपस्थित होने, पत्र एवं अमिलेख प्रस्तुत/अभिलिखित करने, हमारा प्रतिनिधित्व करने, सुलह समझौते सहित सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित/निष्पादित करने तथा सुलह की कार्यवाही से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में सरकारी संस्था से संव्यवहार करने हेतु अधिकृत होंगे।

और, हम एतद्वारा अनुसमर्थन और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं तथा इस मुख्तारनामा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों, समझौता और कार्यवाही का अनुसमर्थन और पुष्टि करते हैं; और यह हमें स्वीकार है कि हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा एतद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए सभी कार्य, समझौता और कार्यवाही हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

हम, ..... (विकासकर्ता का नाम), ने दिनांक.....को निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में इस मुख्तारनामा को निष्पादित किया है।

द्वारा..... (विकासकर्ता का नाम)

(हस्ताक्षर)

वरिष्ठ अधिकारी

गवाह:

1.

2.

स्वीकृत

(हस्ताक्षर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और पता

मेरे सम्पन्न:

नोटरी का नाम और पता

आज्ञा से,

डॉ० एस० एस० सन्धु,  
मुख्य सचिव।



In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Office Memorandum No. 1269/VII-A-2/2021/11(SIIDCUL)/2021 dated October 25, 2021, for General Information.

**OFFICE MEMORANDUM**

*October 25, 2021*

**No. 1269/VII-A-2/2021/11(SIIDCUL)/2021** – Whereas, in view of long pending financial disputes between SIIDCUL and other Government Entities and Private Investors/ Industrialists/ Contractors / Concessionaires/ Lease Holders/ Suppliers/ Consultants etc., a need for establishing a conciliation mechanism of disputes for amicable settlement is being felt.

Therefore, the Government after due consideration, to create investor friendly environment for implementation of development projects in the State, has decided that, in consonance with the spirit of "Ease of Doing Business" and keeping in view the objective of procedural simplification and taking note of various provisions contained in the "Arbitration and Reconciliation Act, 1996 (as amended from time to time)" and recommendations of "Niti Aayog" Government of India, such pending financial disputes may be resolved expeditiously through constitution of a "Conciliation Committee of Independent Expert (CCIE)"; so that the positive atmosphere may be created for private participation for investment and implementation of development works/ program in the State.

Now therefore, in this regard, considering Niti Aayog's OM 14070/14/2016-PPPAU, Dated 05.09.2016 along with Draft report about Conciliation Committee of the Independent Experts circulated through OM No N/14070/04/2021-PPPAU, Dated 20.07.2021, the Governor, is pleased to issue "Conciliation and Settlement Mechanism for Contractual Disputes with the Investors/ Industrialists/ Contractors/ Concessionaires/ Lease Holders/ Suppliers/ Consultants etc in respect of Project of various Government Entities of Uttarakhand."

**Annexure of the Office Memorandum No. 1269 dated 25/10/2021 of the  
Uttarakhand Government**

**Industrial Development Section-2  
Government of Uttarakhand**

**Constitution of Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE)**

**Subject:** Conciliation and Settlement Mechanism for Contractual Disputes with the Investors/Industrialists/Contractors/Concessionaires/Lease Holders/Suppliers/Consultants etc in respect of Projects of various Government Entities of Uttarakhand.

**1. Definitions**

- (a) “State Government” means Government of Uttarakhand;
- (b) “Government Entity” means all Departments/ PSUs/ Boards/ Corporations/ other entities of Government of Uttarakhand;
- (c) “Developers” means all Investors/ Industrialists/ Businessmen/ Contractors/ Concessionaires/ Lease holders/ Consultants etc engaged by Government Entities to deliver/execute projects and Services;
- (d) “Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE)” means Committee of independent experts to be constituted by Competent Authority of Government of Uttarakhand;
- (e) “Projects” means all Construction Contracts/ EPC Contracts/ Public Private Partnerships/ Service/Supply Contracts executed by developers as mandated by Government Entities;
- (f) “Nodal Department” means Director Industries, Department of Industries, Government of Uttarakhand;
- (g) “Nodal officer” means to be declared by every Government Entity to communicate with the Developer and CCIE;
- (h) “Competent authority” means Chief Minister/ Minister/ Secretary/ Head of Department//Managing Director of PSUs or any officer authorised by the State Government;
- (i) “Consent for Conciliation” means with deemed approval from Government Entity and Developer for conciliation as per policies and procedures, as prescribed in Act and SOP;



- (j) "Settlement" means Terms and Conditions mutually agreed by Developer and Government Entity in the presence of CCIE;
- (k) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

## 2. Objective:

A well-developed state infrastructure is a crucial factor for the economic growth of the state. Over the years, efforts have been made to accelerate the pace of development in the entire state through its various Government Entities. These Government Entities have further entered into agreements with Developers to implement projects which have also given rise to disputes between Government Entities and Developers. The problem of pending disputes and claims has assumed serious proportions and has hampered the viability of the aforesaid projects along with delay in the delivery/execution of the projects as well.

Therefore, Government of Uttarakhand, keeping in mind, the *ease of doing business* and to develop *investor friendly environment* to inter alia, generate employment, generation, has decided to constitute a panel of independent experts for conciliation and settlement of the disputes between the Government Entities and Developers.

## Case Example

The State Infrastructure and Industrial Corporation of Uttarakhand Ltd. (SIIDCUL) has entered into various contract agreements with the Developers on behalf of The State for implementing the projects in various modes [Item Rate, Joint Ventures, EPC, etc.]. Several disputes have arisen under these contract agreements which are not only involving exorbitant legal costs, but also causing diversion of precious human and natural resource of both parties involved in these disputes. At present, 11 references have been made to various Arbitral Tribunals further entailing a total claim amount of INR 485 crores. The early and out-of-court settlement/Resolution of disputes is in the interest of all the stakeholders and State's progress.

## 3. Background:

3.1 NITI Aayog while communicating decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) vide its OM No. 14070/1412016-PPPAU dated 5th September 2016, titled "Initiatives on the measures for revival of the Construction Sector - Reg.", directed all the concerned Departments/ Ministries/ Public sector Units to expeditiously examine the initiatives contained therein and take action for their implementation. The initiatives, inter alia, include establishing a system of conciliation of disputes for amicable settlement through appointment of Conciliation Committees comprising of independent experts in order to ensure speedy disposal of pending or new cases.

- 3.2. Directions pertaining to development of conciliation mechanism and Standard Operating Procedures (SOPs) have been issued through Office Memorandum No. - N-14070/04/2021-PPPAU, Dated 20th July, 2021 of Niti Aayog.
- 3.3 The Govt. of Uttarakhand, considering NitiAayog's advisory on establishing the procedure of conciliation of disputes, has decided that the dispute matters pertaining to various projects of the State of Uttarakhand being executed through Government Entities may be referred to the CCIE to settle disputes.

#### **4. Conciliation Committee of Independent experts**

- 4.1 CCIE shall normally be having 3 Members.
- 4.2 Nomination of the members of the committee shall be done by the Uttarakhand Government and the consent of the concerned developer/other party willing for reconciliation shall be obtained on the above conciliation committee. If the developer/ other party has agreed to the Conciliation Committee, then this consent shall be deemed to have been agreed under Section 63 and 64 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).
- 4.3 Term and Tenure of the appointment of Members shall be same as mentioned in their respective appointment orders.
- 4.4 The broad Terms & Conditions and the Terms of Reference of the CCIE are Enclosed at Annexure - 1. The procedures and methodologies so developed shall be deemed to be applicable in conciliation proceedings.
- 4.5 Directorate Industries, Government of Uttarakhand would act as Secretariat for CCIE, and shall arrange for the required infrastructure, Secretarial Assistance and other facilities to the Conciliation Committee. The expenses on such arrangements shall be reimbursed by State Government on half yearly basis.

#### **5. Functioning of the CCIE**

- 5.1 The Conciliation process shall be conducted under Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).
- 5.2 CCIE shall operate with standard operating procedures (SOPs) as prescribed by Government of Uttarakhand as enclosed at Annexure 2.
- 5.3 The possibility of non-availability of any one of the members of a Committee in any proceedings cannot be ruled out. As such, the Committee comprising of the other **two members** shall be competent to proceed in the matter and the proceedings of the Committee shall not be vitiated if one of the three members is not present in the deliberations of the Committee. Whereas, while signing the settlement agreement (between parties), all 3 conciliators shall authenticate the same and the settlement agreement shall be binding on the parties.



- 5.4 The CCIE would either be able to resolve and settle the dispute(s) between the parties, or the process may fail. In case of failure of the conciliation process at the level of the CCIE, the parties may withdraw from conciliation process and take recourse to the laid down legal process of arbitration/ Courts. In the event of the conciliation proceedings being successful, the parties, to the dispute, would sign the written settlement agreement and the conciliators would authenticate the same. Such settlement agreement would then be binding on the parties in terms of Section 73 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

#### **6. Procedure in cases already pending before the Arbitral Tribunals, Courts:**

- 6.1 In cases of disputes pending before the Arbitration Tribunals or the Courts, the Government Entity shall make an offer to the Developer or vice versa to come forward and explore the possibilities of conciliation through the Conciliation Committee as per template communication enclosed at Annexure - 3. The Government Entity and Developer will make an appropriate joint reference to the Conciliation Committee with approval of competent authority, upon which the Committee shall proceed to examine such reference(s) in template communication enclosed at Annexure - 4. However, whenever the parties agree to reach out to the Conciliation Committee, they may request concerned courts/arbitral process to keep the proceedings in abeyance.
- 6.2 In case of settlement, parties shall withdraw the case from concerned courts/ Arbitral process within 30 days of Settlement.

#### **7. Follow-up action by Nodal department on the recommendations of the CCIE:**

- 7.1 The Government Entity and Developer would honour and implement the recommendations/ decisions of the CCIE.
- 7.2 Once the recommendation/decision of the CCIE is received, Nodal department shall inform the Government Entity and Developer along with the brief details of dispute by the party, claim amount, settlement amount etc., within 7 working days.
- 7.3. The Government Entity and Developer shall process the proposal for obtaining the concurrence/approval of the Competent Authority in order to actualise the decision taken by CCIE.
- 7.4 The Government Entity and the Developer shall take prompt action to fulfil their respective obligations for signing of the settlement agreement, as the case may be, including withdrawal of the case(s) pending before the Arbitration Tribunals/ Courts, preferably within a period of 30 days. The payments/commitment due from one party to the other party as per the settlement shall be made/fulfilled by either party within a period of 30 days (or mutually agreed days) from the settlement date.

8. It may be noted that this is an alternate dispute resolution mechanism being put in place by the Government of Uttarakhand and if the Developer is not willing to take recourse to this process or has any reluctance, whatsoever, then, there is no compulsion and they are free to pursue other legal remedies.



**Annexure-1****The Broad Terms and Conditions and the Terms of Reference of CCIE**

1. The CCIE of 3 members shall be constituted by the State Government.
2. Term and Tenure of the appointment of Members shall be same as mentioned in their appointment letter.
3. The conciliation process will be conducted under Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time)
4. A member of the CCIE shall be paid remuneration of INR 25000/- for each day of proceedings.
5. The Conciliation Panel in the first meeting may evolve its own procedures and methodologies for undertaking the functions.
6. The CCIE shall hold its day to day sittings at a suitable place in Dehradun and may hold as many sittings every month as it deems appropriate keeping in view the volume of work at its disposal. It is expected that the Conciliation-cum settlement proceedings shall be completed in each case through 5 sittings in a period of not more than **three months** from the day of reference (Date of receiving of Joint consent letter) is made to the CCIE. In exceptional case, if any particular dispute requires more than 5 sittings, the same may be held at the discretion of the committee with a cap on the payment of remuneration for 7 sittings only, and with the minimum possible time over run.
7. The CCIE may give its recommendations on amicable settlement separately for each contract.
8. The CCIE may develop its own procedures /process for dealing with matters referred to it. However, for the understanding of the parties, it may be noted that the procedure of CCIE may not be treated as alternative arbitration proceedings, whereby both parties come with Statement of Claims/Defence, arguments, rejoinders, written submissions, etc. aided by their respective lawyers. **The forum of CCIE is a settlement forum, where mutual give and take constitutes the essence, rather than strict legal position of the parties.** Hence, the parties are expected to be brief and to the point in front of CCIE with regard to their respective stand and view the exercise in the spirit of conciliation /Settlement.
9. Based on the experience gained in the course of Conciliation proceedings, the Conciliation Committee may suggest/recommend advisories to the State Government or its entities from time to time for improvement in its contract management Systems.

**Annexure-2****Standing Operating Procedures (SOPs) for conciliation**

The following procedure shall be adopted for conciliation of disputes in projects by CCIEs.

1. The procedure for conciliation shall be as prescribed in sections 61 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

**2. Commencement of Conciliation proceedings** in terms of section 62 of the Act

- (a) A letter jointly signed by Developer and Government Entity, consenting to conciliation through CCIE in suggestive template (Annexure - 4).
- (b) Brief statements from Developer and Government Entity, containing issues/ dispute(s) to be taken up for conciliation.

**3. Representation from Developer and Government Entity**

- (a) Government Entity: Representative duly authorised by the competent authority.
- (b) Developer: Must be represented by Senior executive or Regular employee of developer, supported by a Board resolution and Power of Attorney, duly authorised to enter into conciliation agreement. Representative must submit board resolution and power of attorney on or before first hearing in the template format (Annexure - 5 and 6)

**The parties shall not be permitted to engage legal professional during conciliation process**

- 4. Parties may inform the arbitral tribunal/court, if any, regarding initiation of conciliation process by them.
- 5. List of documents (suggestive, not limited) to be submitted by the parties.
  - (a) Copy of contract/concession agreement
  - (b) Copy of Statement of Claim(s) and Statement of Defence(s).
  - (c) Copy of Arbitral award, Statements filed before the Hon'ble court, orders passed by court, if any.
- 6. CCIE may try to reach to an amicable solution as early as possible. For speedy disposal, CCIE may hold frequent meetings.
- 7. CCIE will give recommendation about possible terms of settlement to both parties, wherever necessary, as per section 73 of the Act.

**8. Assistance (in furtherance of Section - 68 of the Act):** The Conciliation Committee shall be assisted by such expert, technical and secretarial assistance, as it may be required for efficient discharge of its functions. The Nodal department may provide arrangements for the same to the satisfaction of the Committee.



**9. Costs of Conciliation and Deposits:**

- 9.1 Nodal Department, in the first instance, shall incur all expenditure on the conciliation proceedings including payment of remuneration to the conciliators, provision of office space, expenditure on dedicated expert and secretarial assistance and other incidental expenses. The other party (Developer) shall also deposit an amount of Rs.3 Lakhs, preferably as an advance, with Nodal department to commence the conciliation proceedings.
- 9.2 The Nodal Department shall maintain the accounts of expenditure incurred on the conciliation proceedings on behalf of the Conciliation Committee. Upon termination of conciliation proceedings, the Nodal department may render an account of the cost of conciliation, which shall finally be decided/ apportioned between/ among the parties as per the directions of the Conciliation Committee.

**10. Residuary matters:**

The CCIE may decide on the procedures to be followed in respect of any residuary matters, including the review of this SOP from time to time, based on the experience gained in the process. Any changes, if required, may be approved by the Competent Authority.

**Annexure 3****Letter to be sent to the Developers with disputes in Department's Projects**

No.

Date:

**Subject: Establishment of Conciliation Committees of Independent Expert (CCIE) for conciliation of disputes pertaining to XXXX Department, Government of Uttarakhand.**

Dear Sir/Madam,

I have been directed to inform you that the Government of Uttarakhand has decided to refer any contractual disputes between the Government Entity and the Developer to the CCIE for conciliation/ settlement of disputes.

1. The Standard Operating Procedures (SOP) for conciliation and settlement of disputes through the conciliatory process and the constitution of the CCIE is attached as Annexure. It may be noted that the scope of the CCIE pervades across disputes before, during or after the Arbitral process.
2. The Government Entity is agree to refer all the cases filed by it before the Hon'ble Courts challenging the Arbitral Awards with appropriate request to the Hon'ble Courts for holding the proceedings in these matters in abeyance for such time as may be taken by the CCIE for settlement of the related disputes in case you are agreeable to the same.
3. Further, in case you are agreeable to refer the disputes presently under Arbitral proceedings to the said Committee, you may also take recourse to this conciliatory and settlement route with appropriate request to the Arbitral Tribunals to consider the holding of the proceedings in abeyance till such time the said dispute(s) is/ are considered by the CCIE.
4. Please take note that by giving your consent/ willingness to refer the dispute(s) to the CCIE, you are also confirming your acceptance of the conciliation process, more specifically to the provisions contained in Sections 63 and 64 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996(as amended from time to time), and that it meets the requirements on "conciliation" under the Act *ibid*.
5. Accordingly, you are requested to indicate your consent/willingness in this regard at the following address of the \_\_\_\_\_ Department.

Address: \_

E-mail: \_

Contact No. \_

Yours Sincerely,

(Nodal officer of the department)



**Annexure-4****Consent letter to CCIE (Signed by both parties, consenting to conciliation)****Before Hon'ble Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE)****Sub: Proposal for settlement of Disputes/Claims pertaining to the subject (Project Name)**

Having consented for conciliation of different disputes/issues of the subject (Project Name) as per the Office Memorandum No. \_\_\_\_\_ Dated\_\_\_\_\_, the parties have agreed for conciliation as per Part - III (Conciliation) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time). This consent of the parties for conciliation is also the consent to the methodology/ standard Operating Procedures to be adopted by the CCIE, as brought out in the above Office Memorandum, issued by the Government of Uttarakhand.

---

**Developer****Government Entity****Authorised Signatory (Sign)****Name****Address****Contact details**

**Annexure 5****Form for Resolution**

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS/ TRUSTEES/SOCIETY OFFICIALS/DESIGNATED PARTNER/INDIVIDUAL (hereinafter called, 'Official') OF \_\_\_\_\_ (Name of the Developer) AT THEIR MEETING HELD ON \_\_\_\_\_ (Date) AT THE \_\_\_\_\_ (Address of the Developer) (hereinafter called, 'address').

"RESOLVED THAT Mr. \_\_\_\_\_ (Name and Designation) (hereinafter referred to as "Authorised Signatory"), resident of \_\_\_\_\_ be and is hereby severally authorised to appear, represent and execute a conciliation agreement on behalf of the \_\_\_\_\_ (Name of Developer), before the Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE), in the best interest of the Developer for the following work.

**Name of the Project:**

KNOW ALL MEN by these present that we, \_\_\_\_\_ (Name of Developer), having our address at \_\_\_\_\_, are represented by Sh \_\_\_\_\_ (Name and Designation of Developer) (hereinafter called, 'Senior Official).

RESOLVED FURTHER THAT the consent of the developer is here by accorded and authorised to Sh \_\_\_\_\_ (Name of Senior official) of the Developer to execute and grant Power of Attorney in favour of \_\_\_\_\_ (Name and Designation of Authorised Signatory).

RESOLVED FURTHER THAT THE SAID Power of Attorney be signed by \_\_\_\_\_ of the Developer.

Specimen Signature

1.

2.

3.

Attested by

\_\_\_\_\_

Signature  
(Senior official)

**Annexure 6****Form for Power of Attorney****POWER OF ATTORNEY**

Know all men by these Presents, We, \_\_\_\_\_ (Name of Developer) having its registered office (or Communication address) at \_\_\_\_\_ ( Hereinafter referred as 'address') are represented by Mr \_\_\_\_\_, son of Shri \_\_\_\_\_ and presently residing at " \_\_\_\_\_", who is presently employed with us and shall hold the position of Authorised Signatory and our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Attorney") to act severally and to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with our incidental to conciliation proceedings for the \_\_\_\_\_ (Project Name) proposed or being developed by the \_\_\_\_\_ (Government Entity) (Hereinafter referred as "Government Entity") including but not limited to signing and submissions of all applications and other documents and writings, participate in meetings, representing us in all matters before CCIE, signing and execution of all documents including the Conciliation Agreement, undertakings consequent to conciliation proceedings, and generally dealing with Government Entity in all matters in connection with or relating to or arising out of conciliation proceedings for the said project.

AND we hereby agree to ratify and confirm and do hereby ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to be have done by us.

IN WITNESS WHEREOF WE, \_\_\_\_\_ (Developer), THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS \_\_\_\_\_ —DAY OF \_\_\_\_\_.

For \_\_\_\_\_ (Developer)

Signature  
(Name and Designation of Senior official of Developer)

Witnesses:

- 1.
- 2.

Accepted

(Signature)  
Authorised Signatory and address

BEFORE ME  
Name and address of Notary

By Order,  
Dr. S.S. SANDHU,  
Chief Secretary



## औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

### कार्यालय ज्ञाप

30 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या-1661/VII-A-1/2021/06ख/12टीसी-तत्काल प्रभाव से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खनिकर्म शाखा में संयुक्त निदेशक (खनन)/मुख्य खान अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय कुमायूँ मण्डल हेतु) वेतन लेवल 12 ₹ 78800-209200 (पूर्व वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे 7600) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संयुक्त निदेशक (खनन)/मुख्य खान अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय कुमायूँ मण्डल हेतु) के पद पर पदोन्नत श्री राजपाल लेघा, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार 06 माह की परीक्षा पर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

### संशोधन/कार्यालय ज्ञाप

18 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या-1982/VII-A-1/2021/06ख/12टीसी-पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या-1661/VII-A-1/2021/06ख/12टीसी., दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत पदोन्नति आदेश में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या-458/एस. बी./2016 सुनील पंवार बनाम राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-03/एस0बी0/2017 दिनेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य का अंकन त्रुटिवश न हो पाने के फलस्वरूप उक्तानुसार की गयी पदोन्नति प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2- उक्तानुसार किये गये टंकण संशोधन की सीमा तक पूर्व संगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को संशोधित किया जाता है। संशोधन के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को भविष्य में संशोधित रूप से पढ़ा और समझा जाय।

### कार्यालय ज्ञाप

28 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या-2032/VII-A-1/2021/6(7)/21-तत्काल प्रभाव से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निदेशक वेतन मैट्रिक्स ₹ 144200-218200 लेवल-15 के रिक्त 01 पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री एस0एल0 पैट्रिक, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,  
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/504-भाग-1-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 13, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आझाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

September 08, 2021

No. 968/III-A-09/SLSA/2021--Ms. Vibha Yadav, Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh is hereby sanctioned Child Care Leave for a period of 90 days w.e.f. 20.05.2021 to 17.08.2021 in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R. K. KHULBEY

Member Secretary.

**BAR COUNCIL OF UTTARAKHAND, NAINITAL****HIGH COURT CAMPUS NAINITAL****CIRCULAR***September 13, 2021***REF.No./B.C.U.K./241/2021-22****Sub: Election of the Chairman, Bar Council of Uttarakhand, Nainital.****Sir,**

At the meeting of the Bar Council of Uttarakhand, Nainital held on Tuesday the 07<sup>th</sup> September 2021, Hon'ble **Shri Prabhat Kumar Chaudhari**, Advocate, Almora is elected as the Chairman of the Bar Council of Uttarakhand Nainital by election.

His residential/office address with telephone numbers is as follows:-

**Hon'ble Shri Prabhat Kumar Chaudhari, Advocate,  
Chairman, Bar Council of Uttarakhand, Nainital**

**Residential/ office address**

**283, Lala Bazar, Almora.**

**Mobile: 9412344777.**

**Email. [prabhatkchaudhari@gmail.com](mailto:prabhatkchaudhari@gmail.com)**

**This is for information and record.**

**MEHARMAN SINGH KORANGA**

*Member Secretary*

**Bar Council of Uttarakhand,**

**Nainital.**



## UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL

CHARGE CERTIFICATE*September 27, 2021*

No. 190/UKPST/Admin.IV/2021/D.Dun—Certified that in compliance of Letter No.4672/XIII-f-1/ Admin.A/2008 Dated September 24, 2021 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand and D.O. Letter No.561/XXX-1-2021 dated 23.09.2021 of the Secretary, Personnel & Vigilance, Govt. of Uttarakhand, Dehradun, the charge of the office of the Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been handed over, as denoted herein, in the forenoon of 27.09.2021.

MAHESH CHANDRA KAUSHIWA,

Relieved Officer.

Countersigned,

illegible

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITYHIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION*October 05, 2021*

No. 1083/III-A-05/2021/SLSA--Ms. Neha Kushawaha, Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for a period of 07 days w.e.f. 20.09.2021 to 26.09.2021.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R. K. KHULBEY

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALCHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

For Child Care Leave.

November 11, 2021

No. 5404/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital was handed over by the undersigned in the evening of 08.10.2021 for availing Child Care Leave of 15 days w.e.f. 16.10.2021 to 30.10.2021 (prefix Second Saturday 09.10.2021 and Sunday 10.10.2021 and Dussehra Holidays w.e.f. 11.10.2021 to 15.10.2021 and suffix 31.10.2021 as Sunday and Deepawali Holidays w.e.f. 01.11.2021 to 05.11.2021 and 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> of November, 2021 are Saturday and Sunday), sanctioned vide letter No. 4690/XIV-71/Admin.A/2003 dated 27.09.2021.

NEENA AGGARWAL,

Registrar (Inspection)

U.H.C Nainital.

Countersigned,

illegible

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

After availing Child Care Leave.

November 11, 2021

No. 5405/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 08.11.2021 after availing Child Care Leave of 15 days w.e.f. 16.10.2021 to 30.10.2021 (prefix Second Saturday 09.10.2021 and Sunday 10.10.2021 and Dussehra Holidays w.e.f. 11.10.2021 to 15.10.2021 and suffix 31.10.2021 as Sunday and Deepawali Holidays w.e.f. 01.11.2021 to 05.11.2021 and 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> of November, 2021 are Saturday and Sunday),

NEENA AGGARWAL,

Registrar (Inspection)

U.H.C. Nainital.

Countersigned,

illegible

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

**NOTIFICATION***November 10, 2021*

**No. 358/XIV-a/1/Admin.A/2009--Shri Rakesh Kumar Singh, 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 23.10.2021 to 01.11.2021 with permission to suffix 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays & 07.11.2021 as Sunday holiday respectively.**

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

*Sd/-*

Registrar (Inspection).

**NOTIFICATION***November 11, 2021*

**No. 359/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Registrar (Inspection) High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 16.10.2021 to 30.10.2021 with permission to prefix 09.10.2021 to 15.10.2021 as holidays of 2<sup>nd</sup> Saturday, Sunday & Dussehra and suffix 31.10.2021 to 07.11.2021 as holidays of Sunday, Deepawali and Saturday-Sunday respectively**

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

*Sd/-*

Registrar General.

**NOTIFICATION***November 15, 2021*

**No. 360/XIV-72/Admin.A/2003--Shri Brijendra Singh, 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 11.10.2021 to 23.10.2021 with permission to prefix 09.10.2021, 10.10.2021 as second Saturday & Sunday respectively and suffix 24.10.2021 as Sunday holiday.**

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

*Sd/-*

Registrar (Inspection)



## कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर

आदेश/कार्यमुक्त

08 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक:-468/कार्यभार/कोषा0बागे0/2021-22-एतद्द्वारा उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8, देहरादून के आदेश संख्या 503/XXVII(6)/1161/एक/2015/2021 दिनांक 07-10-2021 के अनुपालन में श्री भारत चन्द्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वितीय) बागेश्वर की नवीन तैनाती वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के पद (ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-02 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 87700-208700) अपुनरसित वेतनमान 15800-39100 ग्रेड वेतन 8600) पर किये जाने के फलस्वरूप, श्री भारत चन्द्र को नवीन तैनाती स्थल वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के पद पर योगदान देने हेतु आज दिनांक 08-10-2021 के अपराहन में निम्नवत कार्यमुक्त किया जाता है।

कार्यमुक्त अधिकारी

भारत चन्द्र  
वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वितीय)  
बागेश्वर।

कार्यमोचक अधिकारी

(XXX)

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 अस्पष्ट  
वरिष्ठ कोषाधिकारी  
बागेश्वर।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 13, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाणपत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश अजय कुमार दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अजय कुमार धीमान है। भविष्य में मुझे अजय कुमार धीमान पुत्र कैलाश चन्द के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय कुमार धीमान पुत्र कैलाश चन्द,

निवासी खेदाली हरिद्वार,

बहादुराबाद, उत्तराखण्ड।

## कार्यालय नगर पंचायत नन्दप्रयाग (चमोली)

### सार्वजनिक सूचना

17 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 195/सी0एम0सी0-उपनियम/2021-22-नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड-(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत नन्दप्रयाग द्वारा श्फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2020 बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम-2016 की धारा-30(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली को प्रेषित की जा सकेंगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

### अध्याय-1

### सामान्य

#### 1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उपनियम नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली श्फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2020 कहलायेगा।

(2) ये उपनियम नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

#### (1) प्रसंग

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से संबन्धित हैं और परिवार एवं ग्रामीण संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबन्धन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध इन मामलों में सैप्टेज का अनुपालन किया जाता है ताकि सैप्टेज/फीकल स्लज, सैप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

#### (1.1) राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधकीय नीति:



इस पहलू को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है, राष्ट्रीय फीकल एवं सैप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज एवं सैप्टेज और सैप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे जिसमें गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके, जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिये गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

### 1.2 उत्तराखण्ड में सैप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल:

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं010/2015 दिनांक10-12-2015 ने निम्न निर्देश निर्गत किये हैं जो कि उत्तराखण्ड में सैप्टेज प्रबन्ध से संबन्धित हैं। उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित रखने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक या बायोडाइजेस्टर में एकत्र की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्र हुई है वह निशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी संबन्धित नगर पालिका/पंचायत कहलायेगी।

उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 2016 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जलसंस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सैप्टेज प्रबन्ध के लिये तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/पअ(2)-स0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सैप्टेज प्रबन्धन बना रहे जो एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण एवं पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सैप्टेज प्रबन्ध का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें। इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सैप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली जल निगम, जलसंस्थान होंगे।

## 2-नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंध का नियमितीकरण:

सैप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-597/पअ(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत नन्दप्रयाग नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सैप्टेज/फीकल/स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंध उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है आर इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत नन्दप्रयाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

## 3-उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैं:

1. निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे, परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लज और सैप्टेज टैंक से संबन्धित है।
2. क्षेत्र के भालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सैप्टेज परिवहन से संबंधित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें
- 3-उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
- 4-लागत वसूली सुनिश्चित करना जो स्लज के और सैप्टेज के प्रबंध के उचित प्रबंधन हेतु है।
- 5-निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंध में सहभागी सुविधा देना।
- 4.एकत्रीकरण परिवहन इलाज एवं सैप्टेज के खुर्द-खुर्द एक प्रक्रिया अपनाना
- 4.1 सैप्टिक टैंक और सैप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन, जो कोई भी पहले आये।

जबकि स्लज को सुखाना और सैप्टिक टैंक को जो द्रव्य उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल में वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

#### 4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ: पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल स्लज एवं सेप्टेज हेतु जो कि छिद्र निरोधी होंगे और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मापदण्ड का अनुपालन करेंगे।

ब: कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

#### 4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकाल के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 कि0मी0 के अन्तर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जा सकेगा अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

#### 5. सुरक्षा उपाय

1. उचित तकनीकी संयंत्र सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिये जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकाल 2017 में वर्णित है।

2. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि-:

अ: समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफटी गैयर और यंत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा काटेड लियोप्रिन लोपस रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवेल स्कोर्वेजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लेखित है।

ब: समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिये जायें।



स: समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जाय।

द: प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप, आग बुझाने वाले यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं जिससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में आता है।

य: धूमपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो धूमपान वर्जित है।

र: मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिये आना जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल: बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6.0 सैप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1 नगर पंचायत नन्दप्रयाग दर्ज करेगा और लाइसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाइसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि वह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सैप्टेज ट्रांसपोर्ट और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे पंजीकरण प्रपत्र और परमिट, परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.1 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सैप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सैप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सैप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ: प्रारम्भिक पंजीकरण	:रु0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब: नवीनीकरण: रु0 15000.00 प्रति गाड़ी	:रु0 1500.00 प्रति गाड़ी
स: नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	:रु0 1000.00 प्रति गाड़ी

द अन्य शंशोधन आवश्यकतानुसार

:रु0 1000.00 प्रति गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा।)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है उसमें अन्तर आ सकता है

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल स्लज एवं सैप्टेज उपनियम में समय समय पर दर्शाया गया है जो कि सैप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है जो कि निकाय कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से संबन्धित है उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा जो कि समस-समय पर इससे संबन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल सलज एवं सैप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है-

अ: उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकाय फण्ड में जमा किया जायेगा। संबन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से।

ब: निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सैप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी, जो कि उस क्षेत्र स्वामी का है और सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से संबन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सलज एवं सैप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबन्धित होगी जो यह अधिकारी देगा कि वह इसकी लागत वसूल करे और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स: उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना पड़ेगा।

## सारणी 2-उपभोक्ता लागत

क्रम संख्या	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे हेतु निर्धारित है।	मासिक दण्ड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित मूल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशेड वाला मकान	1000	कम से कम दो-तीन वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक दो होते हैं	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाय कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो	125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	2000		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरेंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरे	3500		250
9	होटल/अतिथि गृह 11 से 20 कमरे	4000		250
10	होटल/अतिथि गृह 20 कमरे से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1-25 कमरे	3500		625
12	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/ कालेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/ कालेज	2500		500
17	2 व्हीलर शोरूम	2000		625
18	4 व्हीलर शोरूम	2500		500
19	सिनेमा हाल	3500		625
20	होटल 0-20 कमरे	3500		1250
21	होटल 21-50 कमरे	4000		500
22	होटल 50 कमरे से अधिक	5000		550
23	विवाह हाल/बैकेट हाल	3500		1100



24	बार	3500		625
25	सरकारी हास्पिटल	3000		625
26	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलॉजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 बैड तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 बैड से अधिक	5000		1500
31	चावल की मिल/अन्य मिल	3500		1750
32	अन्य उद्योग(शिडकुल क्षेत्र में)	4000		500
33	अन्य उद्योग(शिडकुल क्षेत्र से बाहर)	3500		1500

नोट:-

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली द्वारा निर्णित किये जायेंगे
2. मल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है( जैसा कि नगर पंचायत नन्दप्रयाग चमोली द्वारा स्वीकृत है
3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाई जायेगी।

मैकेनिज्म का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना

कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगर पंचायत नन्दप्रयाग द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक भवन के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत नन्दप्रयाग में जमा करायी जायेगी।

8.3 नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अपने क्षेत्र के सैप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण, सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी परिवहन निष्पादन और सैप्टेज का इलाज

## 9. दण्ड

दण्ड का दांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल स्लज का एकत्र न करना एवं सैप्टेज का एकत्र न करना और सैप्टेज इलाल प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

## सारणी 3 दण्ड

क्रम संख्या	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रथम दृष्टिया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गई मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरी बार पकड़ी गई विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सैप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	टार0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु तीन महीने हेतु परमिट को निरस्त करना/ परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	
4	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

ह0 अस्पष्ट

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत नन्दप्रयाग,  
जिला-चमोली।

ह0 अस्पष्ट

अध्यक्ष,  
नगर पंचायत नन्दप्रयाग,  
जनपद-चमोली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/504-भाग-8-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।